

## MSME के माध्यम से नरियात को बढ़ाना: नीतिआयोग

### प्रलिस के लयि:

MSME से नरियात को बढ़ावा देना: नीतिआयोग, रकिरंड पर नरियातक (EOR) और रकिरंड पर वकिरेता (SOR) [MSME परदर्शन को बेहतर और तेज़ करने की योजना](#)।

### मेन्स के लयि:

MSME से नरियात को बढ़ावा देना: नीतिआयोग, भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

[स्रोत: द हट्टि](#)

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में [नीतिआयोग](#) ने MSME से नरियात को बढ़ावा देने शीर्षक से एक रपिरट जारी की, जसिमें सफिरशि की गई है क सिरकार को छोटी कंपनयिों के लयि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के माध्यम से अपने माल का नरियात करना आसान बनाना चाहयि।

### रपिरट की प्रमुख सफिरशिं क्या हैं?

- नरियातकों के लयि एकल सूचना पोर्टल:
  - नीति आयोग नरियातकों के लयि एक एकल सूचना पोर्टल के नरिमाण की सफिरशि करता है, जो बाज़ार शुल्क, कागज़ी कार्रवाई आवश्यकताओं, वतित स्रोतों, सेवा प्रदाताओं, प्रोत्साहनों और संभावित ग्राहकों पर व्यापक तथा अद्यतन जानकारी प्रदान करने के लयि **AI-आधारित इंटरफेस का लाभ** उठाता है।
    - इसने MSME के लयि नरियात प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, नरिबाध संचालन और प्रतसिपर्द्धी लाभ की सुवधि हेतु एक व्यापक **राष्ट्रीय व्यापार पोर्टल (NTN)** स्थापति करने की सफिरशि की।
- वार्षिक वतितय समाधान प्रक्रिया:
  - रपिरट में ई-कॉमर्स नरियातकों हेतु वार्षिक वतितय समाधान प्रक्रिया शुरू करने और अस्वीकार या रटिरन के लयि आयात शुल्क पर छूट देने का सुझाव दया गया है। इसमें ई-कॉमर्स नरियात के लयि **ग्रीन चैनल क्लीयरेंस बनाने का भी** प्रस्ताव है।
- रकिरंड पर नरियातक (EOR) और रकिरंड पर वकिरेता (SOR) के बीच अंतर:
  - ई-कॉमर्स नरियात को बढ़ावा देने के लयि रपिरट EOR और SOR के बीच अंतर करने तथा सभी ई-कॉमर्स नरियातों हेतु प्रतशित सीमा के बनि चालान मूलय में कमी की अनुमतदेने का सुझाव देती है।
    - EOR उस पार्टी या इकाई को संदर्भित करता है जसि **आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन में वस्तु के नरियातक के रूप में मान्यता प्राप्त है**। EOR नरियातक देश के सभी नरियात नयिमों, दस्तावेज़ीकरण और सीमा शुल्क आवश्यकताओं के अनुपालन के लयि ज़मिमेदार है।
    - SOR उस पार्टी या इकाई को संदर्भित करता है जसि कानूनी तौर पर वाणज्यिक लेन-देन में वकिरेता के रूप में मान्यता प्राप्त है। SOR खरीदार को सामान बेचने के लयि ज़मिमेदार है और बकिरी की शर्तों पर बातचीत करने, चालान तैयार करने, शपिंग तथा डलिवरी की व्यवस्था करने एवं यह सुनश्चिति करने जैसे कार्यों को संभाल सकता है क सामान सहमत वनरिदेशों को पूरा करता है।
- नरियात ऋण गारंटी को बढ़ावा देना:
  - वतित तक पहुँच को **MSME के लयि एक महत्त्वपूर्ण बाधा** के रूप में उजागर कया गया है। रपिरट में कार्यशील पूंजी की उपलब्धता में सुधार हेतु नरियात ऋण गारंटी को बढ़ावा देने की सफिरशि की गई है, जसिमें सुझाव दया गया है क सिरकार **मौजूदा 10% से 50% या अधिक तक** बढ़ाने के लयि एक प्रोत्साहन पैकेज बनाए।
- MSME के लयि व्यापारिक वस्तुओं के नरियात को आसान बनाना:
  - सुझावों में **सीमति अवर्धा के लयि MSME** हेतु अनुपालन आवश्यकताओं में छूट और कार्यशील पूंजी के अवरोध को रोकने के लयि प्रोत्साहन हेतु समयबद्ध संवतिरण प्रक्रिया लागू करना शामिल है।
- वशिष्ट क्षेत्रों में नरियात अवसरों की पहचान:

- रिपोर्ट वभिन्न क्षेत्रों का अभिनिरिधारण करती है जहाँ भारतीय MSME नरियात बाज़ारों में प्रतस्पर्द्धा कर सकते हैं, जैसे- हस्तशिल्प, हैंडलूम वस्त्र, आयुर्वेद, हर्बल सप्लीमेंट, चमड़े के सामान, नकली आभूषण और लकड़ी के उत्पाद। यह इन क्षेत्रों के लिये 340 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की पर्याप्त वैश्विक बाज़ार क्षमता पर ज़ोर देता है।

## भारत में MSME क्षेत्र का वर्तमान परदृश्य क्या है?

### ■ अर्थव्यवस्था में MSME का योगदान:

- रिपोर्ट भारत की अर्थव्यवस्था में MSME के महत्त्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालती है, जो 11 करोड़ से अधिक नौकरियों और [सकल घरेलू उत्पाद](#) का लगभग 27% है।

### ■ MSME स्थापना में तेज़ी से विकास:

- वित्तीय वर्ष (FY) 2019 और FY 2021 के बीच, भारत में नई MSME इकाइयों की स्थापना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई **लगभग 40 लाख नए MSME स्थापति किये गए**। यह वृद्धि सूक्ष्म उद्यमों में विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
- वर्तमान में, कुल 54 लाख MSME इकाइयों में से लगभग 38% वनिरिमाण क्षेत्र में लगी हुई हैं, जिनमें छोटे और मध्यम उद्यम **पैमाने पर नरियात के लिये उपयुक्त वनिरिमाण गतिविधि में योगदान दे रहे हैं**।
  - वनिरिमाण MSME की उच्चतम सांद्रता वाले शीर्ष 5 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात हैं।

### ■ नरियात क्षमता:

- भारतीय MSME के विकास क्षमता को अनलॉक करने के लिये नरियात महत्त्वपूर्ण है। हालाँकि **बिड़ी कामकाजी उम्र की आबादी और वनिरिमाण MSME में अधिक रोज़गार होने के बावजूद, कम-कुशल वनिरिमाण उत्पादों के वैश्विक नरियात में भारत की हस्तिसेदारी केवल 5% है**।
  - नरियात की संभावना के बावजूद, MSME का केवल एक छोटा प्रतशित ही इसमें संलग्न है, जिनमें **सेकई का नरियात से वार्षिक कारोबार 1 करोड़ रुपए से कम है**।

## MSME क्या है?

- MSME भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो रोज़गार सृजन, औद्योगिक उत्पादन और समग्र आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।
- ये उद्यम वस्तुओं और मर्दों के **उत्पादन, वनिरिमाण, प्रसंस्करण या संरक्षण** में लगे हुए हैं।
  - इनका देश के कुल वनिरिमाण उत्पादन में **हस्तिसे 38.4%** और देश के कुल नरियात में **45.03% का योगदान है**।

## भारत में MSME क्षेत्र से संबंधित वर्तमान चुनौतियाँ क्या हैं?

### ■ वित्तीय बाधा:

- **भारतीय अर्थव्यवस्था** में लघु फर्मों और व्यवसायों के लिये वित्तिपोषण हमेशा एक मुद्दा रहा है। यह व्यवसायों के साथ-साथ MSME क्षेत्र के लिये एक बड़ी बाधा है।
- हालाँकि इसके संबंध में सबसे चिंतीय तथ्य यह है कि **केवल 16% SME को ही समय पर वित्तीय सहायता प्राप्त होती है** जिसके परिणामस्वरूप लघु और मध्यम कंपनियों को अपने स्वयं के संसाधनों पर निर्भर रहने के लिये विवश होना पड़ता है।

### ■ नवाचार का अभाव:

- भारतीय MSME में नवाचार की कमी है और उनके द्वारा उत्पादित अधिकांश उत्पाद पूर्व की प्रौद्योगिकियों पर आधारित हैं। इस क्षेत्र में **उद्यमियों की भारी कमी** है जिससे इसमें नई तकनीकों और उपकरणों को अपनाने में बाधा उत्पन्न होती है।
- अतः MSME को पुरातन प्रौद्योगिकी और कम उत्पादकता स्तर, विशेषकर बड़ी कंपनियों की तुलना में, से **उत्पन्न चुनौतियों** का सामना करना पड़ता है।

### ■ अधिकांश लघु कंपनियाँ:

- **MSME में सूक्ष्म और लघु व्यवसायों की हस्तिसेदारी 80% से अधिक है**। इसलिये संचार अंतराल और जागरूकता की कमी के कारण वे **सरकार की आपातकालीन ऋण व्यवस्था**, दबावग्रस्त प्रसिपत्ति राहत, इक्विटी सहभागिता तथा फंड ऑपरेशन की नधिकि लाभ अर्जति करने में असफल रहते हैं।

### ■ MSME के बीच औपचारिकता का अभाव:

- MSME में औपचारिकता का अभाव है और यह ऋण अंतराल में योगदान देता है।
- देश में लगभग **86% वनिरिमाण MSME अपंजीकृत हैं**। वर्तमान में लगभग 1.1 करोड़ MSME ने ही **वस्तु एवं सेवा कर** हेतु पंजीकरण कराया है।

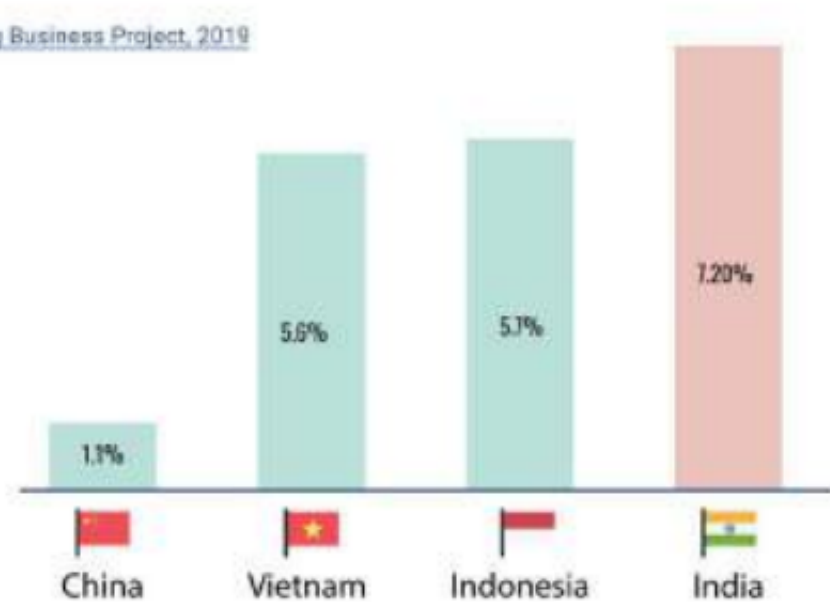


Figure 4.1: Cost of starting a business in India

## MSME से संबंधित सरकारी पहल क्या हैं?

- MSME के प्रदर्शन को बढ़ाने और तेज करने का कार्यक्रम योजना
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिये क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड
- ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण-पत्र
- नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना
- प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिये क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी
- ज़ीरो डेफिक्ट एंड ज़ीरो इफेक्ट

## नष्कर्ष:

भारत में MSME क्षेत्र रोज़गार सृजन और आर्थिक विकास के लिये महत्वपूर्ण है कृति सीमित नरियात भागीदारी तथा नियामक बाधाओं जैसी चुनौतियाँ भी हैं जनिहें इसकी क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिये संबोधित करने की आवश्यकता है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**?????????:**

प्रश्न. वनरिमाण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार की हाल की नीतगित पहल क्या है/हैं? (2012)

1. राष्ट्रीय नविश और वनरिमाण क्षेत्र की स्थापना
2. 'सगिल वडिो क्लीयरेंस' का लाभ प्रदान करना
3. प्रौद्योगिकी अधग्रहण और विकास कोष की स्थापना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन समावेशी विकास के सरकार के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकता है? (2011)

1. स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना
2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना
3. शक्ति का अधिकार अधिनियम को लागू करना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

प्रश्न. भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2023)

1. 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एम.एस.एम.ई.डी) अधिनियम, 2006 के अनुसार, जनिका संयंत्र और मशीनरी में निवेश 15 करोड़ से 25 करोड़ रुपये के बीच है, वे 'मध्यम उद्यम' हैं।
2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दिये गए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन अर्ह हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

**[[[?/?/?/?/?]]]:**

प्रश्न. "सुधारांतर अवधि में सकल-घरेलू-उत्पाद (जी.डी.पी.) की समग्र संवृद्धि में औद्योगिक संवृद्धि पर पछिड़ती गई है।" कारण बताइए। औद्योगिक-नीति में हाल में किये गए परिवर्तन औद्योगिक संवृद्धि को बढ़ाने में कहाँ तक सक्षम हैं? (2017)

प्रश्न. सामान्यतः देश कृषि से उद्योग और बाद में सेवाओं की ओर आंतरिक होते हैं, पर भारत सीधे कृषि से सेवाओं की ओर आंतरिक हो गया। देश में उद्योग की तुलना में सेवाओं की भारी वृद्धि के क्या कारण हैं? क्या सशक्त औद्योगिक आधार के बिना भारत एक विकसित देश बन सकता है? (2014)